गत वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान धान की कम खरीद करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा धान की कम खरीद करने के कारण सरकार ने इस वर्ष चावल का आयात करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो चावल के आयात की मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1788–89 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 1720 लाख टन होने की आशा है।

(ख) सभी प्रमुख फसलों, अर्थात् चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें, के संबंध में 1988–89 में खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। अनुमानित वर्धित उत्पादन का श्रेय पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम और 14 प्रमुख राज्यों में, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू करना तथा किसानों को उपलब्ध कराये गये अधिक सहायता और किसानों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रसार सेवा उपलब्ध कराने सहित सरकार द्वारा अपनाए गए प्रकारमक कार्यक्रमों और नीतियों को जाता है।

(ग) 1988–89 के विपणन मौसम से लेकर 13 जुलाई, 1989 तक के दौरान चावल के रूप में कुल अधिप्राप्ति 76.3 लाख मीटरी टन थी जबकि 1987–88 की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 68.2 लाख मीटरी टन थी। किसानों के स्वैच्छिक प्रस्ताव के आधार पर पर मूल्य समर्थन कार्यों के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति की जाती है जबकि मिल मालिकों और डीलरों पर सांविधिक लेवी के अन्तर्गत चावल की खरीद की जाती है। उत्पादक को यह विकल्प है कि वह अधिप्राप्ति मूल्य पर सार्वजनिक खरीद करने वाली एजेंसियों को धान बेचे अथवा खुले बाजार में जैसाकि उसके लिए लाभदायी हो।

(घ) चावल के समाप्त हुए भंडारों को भरने के लिए 5 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का निर्णय लिया गया है जिसमें से टूटे हुए थाई/विएतनामी चावल के 35 प्रतिशत के 3.76 लाख मीटरी टन के संविदा को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है।

आदिवासियों को अधिक मूल्यों पर चावल की बिक्री

497. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्य सरकारों की बजाय पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों में बिक्री के लिए चावल की पूर्ति करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों में आदिवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर चावल बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के राज्यों के नाम क्या हैं तथा विभिन्न राज्यों में चावल किस मूल्य पर बेचा जा रहा है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कितना अतिरिक्त मूल्य वसूल किया जा रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के मंत्री (श्री सुबोध राम) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार इस स्कीम को शुरू करने की तारीख से 7–8–1986 तक साधारण चावल के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य ले रही थी जबकि उस समय अनुमेय सीमा 185 रुपये प्रति क्विंटल थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत चावल की साधारण, बढ़िया और उत्तम

किस्मों के खुदरा मूल्य क्रमशः 223 रूपये, 289 रूपये और 310 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए हैं। गुजरात सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के लिए खुदरा मूल्यों को पूर्णकि में बदल कर साधारण चावल के लिए 220 रूपये प्रति क्विंटल और बढ़िया किस्म के चावल के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जिससे 1 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षित खुदरा मूल्य ही लागू करें। अन्य राज्यों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

Setting up of an enquiry committee to look into the problems of newsprint

498. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGAT RAM MANHAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up a enquiry Committee to look into the newsprint problems;

(b) if so, what are the terms and conditions of the said Committee; and

(c) by when the Committee is likely to submit its report to Goverenment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (PROF. K. K. TEWARY): (a) to (c) No formal Committee was constituted. However, based on the directives of the P.M., Group of Secretaries comprising of Secretries of Finance, Industrial Development, Commerce and Informatilon & Broadcasting was asked to look into the problems relating to newsprint. Based on the outcome of the discussions of the Group, steps have been taken to provide additional to foreign exchange required for the import of newsprint and to extend customs duty relief on glazed newsprin to the small and medium newspapers, who are entitled to the same as per the Newsprint Allocation Policy for 1989-90.

Impetus to poultry farming

499. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGAT RAM MANHAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that poultry farming in the country had not been given any impetus so far;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) what steps are being taken by Government to give a major breakthrough to poultry farming during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not rise.

(c) Some programmes for augmenting the poultry farming and production have been recommended for the Eighth Five Year Plan which is under finalization.

Funds to Maharashtra for slum development

500. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Government had sanctioned funds to the